भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2652

16 दिसम्बर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: कृषि मंडियों में मूल्य सूचना प्रणाली

2652. श्रीमती अनिता नागरसिंह चौहानः

क्या कृषि और किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार कृषि उपज के मूल्य निर्धारण में पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु देश भर की कृषि मंडियों में मूल्य सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु कोई विशेष कदम उठा रही है;

(ख) यदि हाँ, तो वास्तविक समय मूल्य सूचना प्रदर्शित करने वाली डिजिटल प्रणाली से जुड़ी मंडियों की संख्या कितनी है;

(ग) क्या ई-नाम प्लेटफॉर्म के विस्तार के लिए कोई समयबद्ध योजना निर्धारित की गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का किसानों को निःशुल्क मोबाइल-आधारित मूल्य सूचना सेवाएँ प्रदान करने हेतु कोई नई पहल शुरू करने का विचार है; और

(ङ) सरकार द्वारा मूल्य पारदर्शिता बढ़ाने के लिए प्रस्तावित या कार्यान्वित किए जा रहे अन्य उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) एवं (ख): सरकार किसानों के लिए मूल्य सूचना के महत्व को समझते हुए, वर्ष 2000 से देश में विपणन अनुसंधान एवं सूचना नेटवर्क (एमआरआईएन) कार्यान्वित कर रही है। इस योजना के अंतर्गत विकसित और संचालित एगमार्कनेट पोर्टल, कृषि उपज बाजार समितियों (एपीएमसी) को एकीकृत करके किसानों को वास्तविक समय में मूल्य सूचना प्रदान करता है। नवंबर 2025 में इस पोर्टल को तकनीकी रूप से उन्नत करके एगमार्कनेट पोर्टल 2.0 बना दिया गया है। पोर्टल के साथ नई मंडियों का एकीकरण एक सतत प्रक्रिया है। अब तक देश भर में 4367 मंडियों को एगमार्कनेट पोर्टल से जोड़ा जा चुका है ताकि वास्तविक समय में मूल्य सूचना प्रदर्शित की जा सके। खेतों से ही वास्तविक समय में मूल्य और अराइवल की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा के लिए, सरकार ने एगमार्कनेट 2.0 मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है। यह ऐप मंडी डेटा को मौके पर ही दर्ज करने में सक्षम है और किसानों को बेहतर विपणन निर्णय लेने के लिए अपने मोबाइल फोन पर मूल्य और अराइवल की जानकारी प्राप्त करने की सुविधा देता है।

(ग) से (ङ): ई-राष्ट्रीय कृषि बाजार (ई-नाम) एक मांग-आधारित योजना है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर नई मंडियों का एकीकरण राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर उनकी मांग और तत्परता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। इसके विस्तार के लिए कोई विशिष्ट समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित नहीं है। अब तक 1522 मंडियों को ई-नाम पोर्टल पर जोड़ा जा चुका है।

किसानों के लिए मूल्य पारदर्शिता बढ़ाने के उद्देश्य से ई-नाम पोर्टल और मोबाइल ऐप पर ट्रेड की गई सभी व्यापारिक वस्तुओं के वास्तविक समय के मंडी मूल्य प्रदर्शित करता है। ऑनलाइन बोली उचित मूल्य निर्धारण सुनिश्चित करती है और किसानों को समय पर भुगतान के लिए ई-भुगतान की सुविधा प्रदान करती है।

ई-नाम मोबाइल एप्लिकेशन के माध्यम से 247 अधिसूचित वस्तुओं के लिए निःशुल्क मोबाइल-आधारित मूल्य सूचना सेवा प्रदान की जा रही है। यह ऐप किसानों को आस-पास की ई-नाम मंडियों की पहचान करने, प्रचलित कीमतों और पहुंच का मार्ग देखने में भी सक्षम बनाता है।

*****